मिल नहीं कोल्हू में जा रहा गन्ना

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 10 अक्टूबर

महाराष्ट्र के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों ने गुड़ इकाइयों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के मुकाबले 18 फीसदी कम पर अपनी उपज की आपात बिक्री शुरू कर दी है।

गुड़ इकाइयां (कोल्हू) अधिक गुणवत्ता वाले गन्ने को मौजूदा समय में 180 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद रही हैं जबकि कृषिगत लागत एवं कीमत आयोग (सीएसीपी) द्वारा पेराई सत्र 2014-15 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 220 रुपये प्रति क्विंटल का एफआरपी घोषित किया गया है।

किसानों की इस पहल का मकसद दिसंबर से पहले गेहूं की जल्द बुआई के लिए खेतों को खाली करना है। वे 150-160 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत पर भी गुड़ इकाइयों के साथ वायदा अनुबंध कर रहे हैं, क्योंकि चीनी मिलों ने तब तक पेराई शुरू नहीं किए जाने की योजना बनाई है जब तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्णायक गन्ना नीति की घोषणा नहीं कर देतीं।

जारी गतिरोध

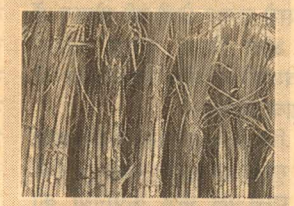

- एफआरपी से 18 फीसदी कम मूल्य पर कोल्हुओं को गन्ना बेच रहे किसान
- राज्य सरकार और चीनी मिलों के बीच जारी गतिरोध के कारण मिलों ने पेराई शुरू नहीं की
- 95 निजी चीनी मिलों में से 66 फीसदी मिलों में चालू है रखरखाव कार्य

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महासचिव अविनाश वर्मा ने कहा, 'हमने इस साल जुलाई में सरकार को एक संयुक्त बयान सौंपा था जिसमें हमने इस सीजन में पेराई शुरू करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। लगभग तीन महीने बीत चुके हैं। इस बारे में कई बैठकें हुई हैं। लेकिन गन्ना नीति पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। जब तक किसी ठोस गन्ना नीति का फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक चीनी मिलें इस सीजन में पेराई शुरू करने में सक्षम नहीं होंगी।' बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, सिंभावली शुगर्स और द्वारिकेश शुगर जैसी निजी चीनी मिलों ने कई वर्षों से लगातार नुकसान में रहने की वजह से इस साल जुलाई में अपनी चिंता प्रकट की थी।

95 निजी चीनी मिलों में से 66 मिलों ने अभी तक 'मैंटेनेंस कार्य' शुरू नहीं किया है। मैंटेनेंस कार्य के तहत पेराई से पहले मशीनों की सफाई और गन्ना भंडारण इलाके को खाली करने की प्रक्रिया आदि को पूरा किया जाता है जिसे चालू सत्र के लिए गन्ना उत्पादन की शुरुआत का संकेत माना जाता है।

उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के लिए गन्ना किसान प्रमुख वोट बैंक हैं। इसलिए राज्य में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल तय की है जो केंद्र द्वारा निर्धारित एफआरपी के मुकाबले 27 फीसदी अधिक है। चीनी कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से चीनी मिलों की प्राप्तियों में कमी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए मिलों ने इस साल परिचालन शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है।

Business Standard
11-10-14